फेड के रुख से राहत में रुपया

अमेरिका में दरों पर नजरिया बदला, फॉरवर्ड प्रीमियम 5 महीने के उच्चस्तर पर

भास्कर दत्ता
मुंबई, 23 मार्च

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये मे गुरुवार को खासी मजबूती दर्ज हुई क्योंकि फेडरल रिजर्व के हालिया मौद्रिक नीति बयान ने उम्मीद जगाई है कि केंद्रीय बैंक दरों में सख्ती के अपने चक्र के आखिरी पायदान पर है। डीलरों ने यह जानकारी दी।

देसी मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.26 पर टिकी, जो एक दिन पहले 82.67 पर बंद हुई थी। गुरुवार की चाल 3 मार्च के बाद डॉलर के मुकाबले सबसे तेज एकदिवसीय बढ़त और 13 मार्च के बाद सबसे मजबूत बंद भाव को प्रदर्शित करती है। साल 2022 में डॉलर के मुकाबले करीब 10 फीसदी टूटने के बाद रुपये ने मौजूदा कैलेंडर वर्ष में अभी तक 0.6 फीसदी की तेजी दर्ज की है।

बुधवार देर शाम अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों का इजाफा किया और फेडरल फंड की दरें अब 4.75-5.00 फीसदी है। इस बढ़ोतरी के साथ मार्च 2022 से अब तक ब्याज दरों में 475 आधार अंकों का इजाफा हो चुका है।

फेड ने भले ही ब्याज दरें बढ़ाई, लेकिन भविष्य में सख्ती को लेकर फेड का रुख पहले के मुकाबले नरम माना जा रहा है, खास तौर से हालिया अमेरिकी बैंकिंग संकट के आलोक में।

डॉलर बनाम रुपया

- देसी मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.26 पर टिकी, जो एक दिन पहले 82.67 पर बंद हुई थी
- शिन्हान बैंक के उपाध्यक्ष कुणाल सोढानी का अनुमान है कि इस महीने के आखिर तक रुपये का दायरा प्रति डॉलर 81.80 से 82.80 रहेगा
- साल 2022 में डॉलर के मुकाबले करीब 10 फीसदी टूटने के बाद रुपये ने मौजूदा कैलेंडर वर्ष में अभी तक 0.6 फीसदी की तेजी दर्ज की है

येस बैंक के अर्थशास्त्री ने कहा, कीमत में स्थिरता पर लगातार फेड की नजर बनी हुई है, लेकिन आगे के अनुमान को लेकर भाषा बदली है। ज्यादातर विश्लेषक अब उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी महीनों में एक बार 25 आधार अंकों का इजाफा होगा जबकि कुछ का मानना है कि अब और सख्ती नहीं होगी।

बाजार के कुछ सेगमेंट साल 2023 में आगे फेड की तरफ से दरों में कटौती मानकर चल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम में उतारचढ़ाव ने सख्त वित्तीय हालात पैदा कर दिए हैं और गुरुवार को अमेरिकी डॉलर इंडेक्स काफी कमजोर हुआ। 3.30 बजे इंडेक्स 102.37 पर था, जो गुरुवार को इस वक्त 103.28 रहा था।

एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष (ओवरसीज ट्रेजरी) भास्कर पांडा ने कहा, मुझे लगता है कि आगे रुपये का दायरा 81-83 प्रति डॉलर होगा। भुगतान संतुलन में सुधार हुआ है क्योंकि तेल की कीमतें घटी हैं, लेकिन जब तक पूंजी खाते में प्रवाह दोबारा नहीं होता तब तक आप रुपये के आयाम में तब तक ज्यादा बदलाव नहीं देखेंगे जब तक कि अमेरिकी ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं।

शिन्हान बैंक के उपाध्यक्ष कुणाल सोढानी का अनुमान है कि इस महीने के आखिर तक रुपये का दायरा प्रति डॉलर 81.80 से 82.80 रहेगा।

फॉरवर्ड प्रीमियम में उछाल

अब बाजार समझने लगा है कि फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अपने आखिरी चक्र में पहुंच रहा है, ऐसे में डॉलर-रुपये का फॉरवर्ड प्रीमियम पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से बढ़ा है। फॉरवर्ड प्रीमियम भारत व अमेरिका के ब्याज दरों में अंतर को प्रतिबिंबित करता है।

साल 2022 में फॉरवर्ड प्रीमियम 11 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया था क्योंकि दरों में अंतर काफी तेजी से सिकुड़ा था। इसकी वजह आरबीआई के मुकाबले फेड की तरफ से तेज गति से ब्याज बढ़ोतरी थी। आरबीआई ने मई 2022 के बाद से ब्याज दरों में 250 आधार अंकों का इजाफा किया है। ब्याज दरों में कम अंतर विदेशी निवेशकों को भारतीय परिसंपत्ति की ओर कम आकर्षित करता है।

8 मार्च के बाद से एक साल का फॉरवर्ड प्रीमियम 34 आधार अंक उछला है जब सिलिकन वैली बैंक धराशायी हुआथा। मंगलवार को दर 2.48 फीसदी थी, जो 20 अक्टूबर, 2022 के बाद का उच्चस्तर है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

बैंकिंग संकट के बाद भी फेड ने बढ़ाई दरें, बाजार टूटे मगर कम

बीएस संवाददाता
मुंबई, 23 मार्च

बेंचमार्क सेंसेक्स गुरुवार को आधा फीसदी टूट गया क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 आधारअंकों का इजाफा किया है, जो मार्च 2022 के बाद की लगातार नौंवी बढ़ोतरी है। फेड ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में महंगाई पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया है। हालिया बढ़ोतरी के बाद अब ब्याज दरें 4.75 से 5 फीसदी हो गई है, जो 2007 के बाद सबसे ज्यादा है और बैंकिंग क्षेत्र में संकट के बाद भी ब्याज में बढ़ोतरी की गई है। बाजार में गिरावट हालांकि थोड़ी थमी क्योंकि निवेशकों का मानना है कि फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का काम पूरा कर लिया है जबकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए।

बेंचमार्क सेंसेक्स 289 अंक यानी 0.5 फीसदी टूटकर 57,925 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 75 अंकों की गिरावट के साथ 17,077 पर टिका।

बाजारों का भरोसा फेड के नरम रुख से बढ़ा और इस अनुमान से भी कि केंद्रीय बैंक धीरे-धीरे ब्याज दरों में कटौती की ओर कदम बढ़ाएगा।

बैंक ऑफ इंगलैंड ने भी अमेरिका व नॉर्वे की तरह ब्याज दरों में 25 आधार अंकों का इजाफा कर दिया क्योंकि महंगाई उच्चस्तर पर बनी हुई है।

नॉर्वे के बैंक ने बेंचमार्क जमा दरें गुरुवार को 25 आधार अंक बढ़ाकर 3 फीसदी पर पहुंचा दी, जो 2009 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। साथ ही संकेत भी दिया कि उच्च कीमत के दबाव के खिइलाफ और सख्ती हो सकती है।

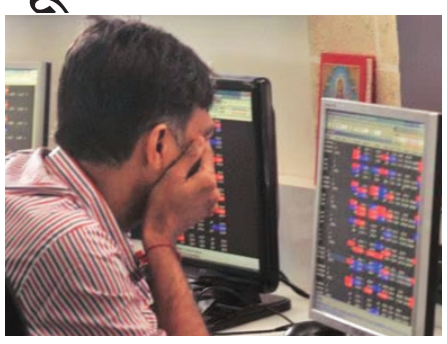

विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने महंगाई के अनुमान को संतुलित करने और वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

निवेशक अब साल के आखिर तक ब्याज दरों में कटौती का अनुमान लगा रहे हैं। बाजार के एक वर्ग का मानना है कि फेड की दरें दिसंबर तक घटकर 4.1 फीसदी रह जाएगी।

फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल ने खुद कहा कि उन्हें इस साल दरों में कटौती नहीं दिखती और जरूरत पड़ी तो वह ब्याज बढ़ाएंगे।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के खुदरा शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा, देसी इक्विटी बढ़त व नुकसान के बीच झूलते रहे जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज बढ़ोतरी जारी रखी। ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान में कहा गया कि सभी बैंकों की जमाओं पर बीमा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जिससे सेंटिमेंट खराब हुआ। फेड ने बाजार को ठोस दिशा के लिए काफी कुछ नहीं किया। महंगाई पर लगाम का उनका लक्ष्य बरकरार है जबकि बैंकिंग संकट भी है।

अदाणी पावर को फिर एएसएम में रखेंगे एक्सचेंज

एनएसई और बीएसई ने कहा कि अदाणी पावर को गुरुवार, 23 मार्च से अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी कदम (एएसएम) के दायरे में रखा जाएगा। शेयर बाजारों के परिपत्रों में यह जानकारी दी गई। इससे पहले, एनएसई और बीएसई ने अदाणी समूह की दो कंपनियों- अदाणी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों को सोमवार से दीर्घकालिक अतिरिक्त निगरानी कदम (एएसएम)व्यवस्था के पहले चरण से बाहर रखने का निर्णय लिया था। शेयर बाजारों ने अदाणी पावर, अदाणी एंटर. और अदाणी विल्मर को 8 मार्च को एएसएम के तहत रखा था, हालांकि 17 मार्च को तीनों को निगरानी के दायरे से बाहर कर दिया था। *भाषा*

फिच ने की अदाणी पोर्ट्स की रेटिंग की पुष्टि

फिच रेटिंग्स ने अदाणी पोर्ट्स की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्युअर डिफॉल्ट रेटिंग बीबीबी - की पुष्टि की है। यह बताती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का एपीएसईजेड की फंडिंग लागत व मौजूदा रेटिंग पर एक्सेस के मामले में अल्पावधि में असर सीमित रहेगा। *बीएस*

निफ्टी ऑप्शंस गड़बड़ी मामले को मॉर्गन स्टैनली ने निपटाया

मॉर्गन स्टैनली फ्रांस ने निफ्टी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में कथित गड़बड़ी वाले मामले में 25.35 लाख रुपये का भुगतान कर मामला निपटा दिया है। यह ट्रेड साल 2017 में हुआ था और इसका निपटान सेबी के निपटान नियमन के तहत हुआ है, जहां कथित तौर पर गड़बड़ी करने वाला गलती स्वीकार कर या इससे इनकार कर मामला निपटा सकता है। जुलाई 2017 और अगस्त 2017 के बीच मॉर्गन स्टैनली फ्रांस और रिलायंस स्ट्रैटिजिक इन्वेस्टमेंट्स ने सेबी के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन कर निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड किया था। बताया गया कि दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से इलिक्विड निफ्टी पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में 11,400 के स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड किया, जो इसकी आंतरिक वैल्यू के मुकाबले कम थी। बीएस

सिर्फ केवाईसी अनुपालन वाले ई-वॉलेट से निवेश स्वीकारे एमएफ

बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंडों को निर्देश दिया है कि वह सिर्फ ऐसे ई-वॉलेट से निवेश स्वीकार करे, जिसने आरबीआई के नो योर कस्टमर (केवीआई) नियमों का अनुपालन किया हो। म्युचुअल फंड के नियम एक साल में 50,000 रुपये तक का निवेश नकद या ई-वॉलेट के जरिये की इजाजत देते हैं। म्युचुअल फंडों में ई-वॉलेट के जरिये निवेश की इजाजत साल 2017 में दी गई थी ताकि डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिले। *बीएस*

आईडीएफसी फाइनैंशियल को तरजीही आधार पर शेयर जारी करेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

बीएस संवाददाता
मुंबई, 23 मार्च

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने आईडीएफसी फाइनैंशियल होल्डिंग कंपनी को 10 रुपये मूल्य वाले 37.75 करोड़ शेयर तरजीही आधार पर आवंटित करने की मंजूरी दी है। ये 58.18 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से निजी नियोजन के जरिए आवंटित किए जाएंगे। आईडीएफसी फाइनैंशियल, आईडीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है।

इससे पहले आईडीएफसी लिमिटेड ने बैंक में पूंजी के तौर पर 2,200 करोड़ रुपये निवेश करने

का फैसला लिया था, जिसके बाद शेयर आवंटित करने की घोषणा हुई है। इसके बाद बैंक में आईडीएफसी होल्डिंग की हिस्सेदारी बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 40 फीसदी हो जाएगा। इक्विटी शेयर के तरजीही आवंटन के लिए बैंक को पहले ही स्टॉक एक्सचेंजों से

सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। बैंक ने कहा, आवंटित शेयरों की सूचीबद्धता के लिए आवेदन व उसकी ट्रेडिंग की मंजूरी इस दरम्यान ली जाएगी।

जोमैटो के शेयर में दिख रहे तेजी के आसार

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 23 मार्च

जोमैटो का शेयर इस कैलेंडर वर्ष में अब तक 9 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुका है और बीएसई के सेंसेक्स की तुलना में उसका प्रदर्शन कमजोर है। सेंसेक्स में समान अवधि के दौरान करीब 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इस कमजोर प्रदर्शन के बावजूद एचएसबीसी के विश्लेषकों का मानना है कि यह शेयर 87 रुपये पर पहुंच सकता है जो उसके मौजूदा स्तरों की तुलना में 64 प्रतिशत की तेजी है। एचएसबीसी के विश्लेषकों योगेश अग्रवाल और अभिषेक पाठक ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि फूड डिलिवरी उद्योग ने पिछले कुछ महीनों से कमजोरी दर्ज की है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'चालू वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में हमें सकल

बदलाव की उम्मीद

- एचएसबीसी ने इस शेयर में 64 प्रतिशत तेजी आने का अनुमान जताया है
- अपनी गोल्ड सदस्यता से रेस्टोरेंट एग्रीगेटर को बाजार में दबदबा फिर से बढ़ाने में मदद मिली है

ऑर्डर वैल्यू (जीओवी) सालाना आधार पर करीब 9 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, जो 15 प्रतिशत के हमारे मध्यावधि अनुमानों से कम है। जोमैटो में निवेशकों के लिए कई बदलाव दिखे हैं।' दिसंबर 2022 में समाप्त तीसरी तिमाही में जोमैटो का नुकसान पूर्ववर्ती अवधि के 63.2 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 346.6 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 250.8 करोड़ रुपये का नुकसन दर्ज किया। विश्लेषकों का कहना है कि ब्लिंकइट को शामिल किए जाने की वजह से नुकसान सालाना आधार पर करीब 5.5 गुना बढ़ गया। इस बीच, राजस्व 75 प्रतिशत बढ़कर 1,948.2 करोड़ रुपये हो गया, जो सालाना आधार पर 1,112 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

एचएसबीसी का कहना है कि जोमैटो ने स्विगी के हाथों गंवाई अपनी बाजार भागीदारी में अब सुधार दर्ज किया है। कंपनी को जोमैटो गोल्ड की पेशकश से मदद मिली है। 2021-22 में जोमैटो की बाजार भागीदारी 55 प्रतिशत थी, जबकि स्विगी के लिए यह आंकड़ा 45 प्रतिशत था। एचएसबीसी का कहना है कि 2023-24 में जोमैटो के लिए बाजार भागीदारी का आंकड़ा बढ़कर 57 प्रतिशत, जबकि प्रतिस्पर्धी स्विगी के लिए 43 प्रतिशत रह सकता है।

कैलेंडर वर्ष में स्टार्टअप फंडिंग में कमजोरी बरकरार

आर्यमन गुप्ता
नई दिल्ली, 23 मार्च

देश के स्टार्टअप तंत्र में इस कैलेंडर वर्ष में फंडिंग में तेजी नहीं आई है। इससे सात वर्षों में सर्वाधिक गैर निवेशित उद्यम पूंजी एकत्रित हो गई है, क्योंकि निवेशक स्टार्टअप कंपनियों के सही मूल्यांकन का इंतजार कर रहे हैं।

भारत में प्रमुख निवेशकों के सबसे बड़े नेटवर्क इंडियन ऐंजल नेटवर्क के सह-संस्थापक पदमजा रूपारेल का कहना है, 'निवेशक अब उन कंपनियों में निवेश करने को इच्छुक हैं जो अच्छे राजस्व एवं मुनाफे से जुड़ी हुई हों। इससे मूल्यांकन ज्यादा वास्तविक बन गए हैं।'

मार्केट इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के आंकड़े के अनुसार, इस साल 1 जनवरी से 21 मार्च के बीच 231 फंडिंग सौदे हुए। हालांकि इनसे धारणा को मजबूत बनाने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि उद्यमियों के साथ साथ निवेशक भी यह मान रहे हैं कि फंडिंग में कथित कमजोरी अभी बरकरार रहेगी। इस साल फंडिंग 10.5 अरब डॉलर के मुकाबले कम रही। पिछले साल 1 जनवरी से 21

फंडिंग

- भारत-केंद्रित उद्यम वीसी कंपनियों के पास 12.88 अरब डॉलर की नकदी मौजूद है, जो 7 साल में सर्वाधिक है
- यदि 2022 से तुलना करें तो इस कैलेंडर वर्ष में बड़े आकार के सौदों की संख्या में तेजी लाए जाने की जरूरत है

मार्च के दौरान 696 सौदों के जरिये 10.5 अरब डॉलर की फंडिंग हुई थी। इसके अलावा, यूनिकॉर्न की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से अधिक होती है। वर्ष2022 के मध्य में फंडिंग में नरमी आने से पहले तक स्टार्टअप क्षेत्र के लिए यूनिकॉर्न बेहद आकर्षक थीं। वर्ष 2022 में 23 यूनिकॉर्न शामिल हुईं, और 2021 में यह संख्या 42 थी।

कम से कम 80 स्टार्टअप में शुरुआती चरणों में निवेश कर चुकी 100एक्स डॉट वीसी के सह-संस्थापक शशांक रनडेव ने कहा, 'पूर्व में, कई कंपनियों ने दबाव में आकर ऊंचे मूल्यांकन पर कोष जुटाए। निवेशक अब मान रहे हैं कि इसके लिए कम मूल्यांकन जरूरी है और वे व्यवसाय के मुख्य आधार को देखते हैं।' यूनिकॉर्न की संख्या नहीं बढ़ने के बावजूद, इस साल बड़े निवेश राउंड हुए। अपने मौजूदा 1 अरब डॉलर के राउंड के तहत फोनपे अब तक तीन बार में 65 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए सुर्खियों में रही है। लेंसकार्ट ने पिछले सप्ताह अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से 50 करोड़ डॉलर जुटाए। बीमा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंश्योरेंसदेखो ने पिछले महीने सीरीज ए राउंड में 15 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाई।

हालांकि यदि 2022 की तुलना करें तो बड़े आकार के सौदों की संख्या में तेजी आना बाकी है। 2022 में 10 करोड़ डॉलर आकार के 61 निवेश राउंड दर्ज किए गए, और 2021 में ऐसे 105 राउंड दर्ज किए गए। रेवफिन सर्विसेज के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी समीर अग्रवाल ने कहा, 'ज्यादातर स्टार्टअप को मौजूदा समय में कोष जुटाने में समस्या हो रही है, और जो कोष जुटाया भी जा रहा है, वह आकर्षक मूल्यांकन पर नहीं मिल रहा है।'

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan the QR Code to view the DRHP)

MS GROUP

MOTISONS JEWELLERS LIMITED

Our Company was originally formed as "M/s Motisons Jewellers", a partnership firm pursuant to partnership deed dated October 16, 1997 and was registered under the Indian Partnership Act, 1932 with the Registrar of Firms, Jaipur. "M/s Motisons Jewellers" was converted into a public limited company under the Companies Act, 1956 with the name "Motisons Jewellers Limited" pursuant to a certificate of incorporation dated May 09, 2011 issued by the Registrar of Companies, Rajasthan at Jaipur ("**RoC**") bearing Corporate Identification Number **U36911RJ2011PLC035122**. For details of Incorporation, change of name and registered office of our company, please refer to chapter titled ***"History and Certain Other Corporate Matters"*** beginning on page 193 of the Draft Red Herring Prospectus ("**DRHP**") dated March 22, 2023 filed with Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**").

Registered Office: 270, 271, 272 & 276 Johri Bazar, Jaipur 302003, Rajasthan, India.
Corporate Office: SB-110, Motisons Tower, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur – 302015, Rajasthan, India. **Tel. No.:** +91 – 141 – 4150000, **E-mail:** nehajaincs@motisons.com,
Website: www.motisonsjewellers.com, **Contact Person:** Ms. Neha Jain, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SANDEEP CHHABRA, MR. SANJAY CHHABRA, MS. NAMITA CHHABRA, MS. KAJAL CHHABRA, MOTI LAL SANDEEP CHHABRA HUF, SANDEEP CHHABRA HUF AND SANJAY CHHABRA HUF

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 3,34,71,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE), AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF UP TO 60,00,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"). IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE ISSUE SIZE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT, SUBJECT TO THE ISSUE COMPLYING WITH RULE 19(2)(b) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED ("SCRR").

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●], THE ENGLISH NATIONAL NEWSPAPER, ALL EDITIONS OF [●], THE HINDI NATIONAL NEWSPAPER AND [●] EDITIONS OF [●], THE REGIONAL NEWSPAPER, (HINDI BEING THE LOCAL LANGUAGE OF RAJASTHAN, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS SITUATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST 2 (TWO) WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE" TOGETHER WITH "BSE", THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid / Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid / Issue Period not exceeding 10 working days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid / Issue Period not exceeding 10 working days. Any revision in the Price Band and the revised Bid / Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE OF ₹ [●] EACH IS [●] TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (SEBI ICDR Regulations) and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs** and such portion, the "**QIB Portion**"), provided that our Company in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("**Anchor Investor Portion**"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("**Anchor Investor Allocation Price**"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) ("**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. The Equity Shares available for allocation to Non-Institutional Bidders under the Non-Institutional Portion, shall be subject to the following: (i) one-third of the portion available to Non-Institutional Bidders shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 2.00 Lakhs and up to ₹ 10.00 Lakhs, and (ii) two-third of the portion available to Non-Institutional Bidders shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 10.00 Lakhs, provided that the unsubscribed portion in either of the aforementioned sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders. All potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or by the Sponsor Banks under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA Process. For details, see ***"Issue Procedure"*** on page 366 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and the DRHP dated March 22, 2023 has been filed with the SEBI.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and the website of BRLM, i.e. Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company, the BRLM and Registrar to the Issue at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, and/or our Company and/or the BRLM and/or Registrar to the Issue and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company in relation to the Issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. **Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* on page 35 of the DRHP.**

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the Red Herring Prospectus ("**RHP**") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see "***History and Certain Corporate Matters***" on page 193 of the DRHP.

The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, please see "***Capital Structure***" on page 89 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
	LINK Intime
HOLANI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 401 – 405 & 416 – 418, 4th Floor, Soni Paris Point, Jai Singh Highway, Bani Park, Jaipur – 302016 **Tel.:** +91 0141 – 2203996; **Fax:** +91 0141 – 2201259 **Website:** www.holaniconsultants.co.in **Email:** ipo@holaniconsultants.co.in **Investor Grievance ID:** complaints.redressal@holaniconsultants.co.in **Contact Person:** Mrs. Payal Jain **SEBI Registration No.:** INM000012467	**LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** C – 101, 247 Park, 1st Floor, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 49186200; **Fax:** +91 22 49186195 **Website:** www.linkintime.co.in **Email:** motisons.ipo@linkintime.co.in **Investor Grievance ID:** motisons.ipo@linkintime.co.in **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration Number:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **MOTISONS JEWELLERS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ms. Neha Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Jaipur
Date : March 23, 2023

MOTISONS JEWELLERS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and the DRHP dated March 22, 2023 has been filed with SEBI. The DRHP shall be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, stock exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and is available on the websites of the BRLM, i.e. Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "***Risk Factors***" beginning on page 35 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

CONCEPT